नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

New Delhi Municipal Council

बजट भाषण

Budget Speech

2017 - 18

To be The Global Benchmark for a Capital City

Vision to Action

- 4 Zero Waste Colonies
- Palika Play Schools
- Mechanisation of Horticulture and Sanitation Operations
- Happiness areas in big gardens
- NDMC dashboard for Citizen Outreach
- Smart addressing solution for Properties

Energy Savings

- Warm Led Street Lights
- Promotion of Rooftop solar panels on private buildings
- Green NDMC Buildings

Team NDMC

- Foreign training for the field officials
- International sister city agreements for peer learning and knowledge transfer
- Three housing schemes for NDMC Employees
- Creation of Pension Fund

श्रम एव जयते

NDMC

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

श्री नरेश कुमार

अध्यक्ष

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

द्वारा

बजट भाषण

दिनाँक : 13 जनवरी, 2017

स्मार्ट सिटी मिशन

ई-गवर्नेंस, एम-गवर्नेंस तथा जन-साधरण सहभागिता के माध्यम से सुशासन।

स्मार्ट टैक्नोलॉजी

न.दि.न.परिषद् की शहर संरचना

सामाजिक विकास

पर्यावरणीय स्थिरता

टीम एनडीएमसी

वित्तीय स्थिरता

अन्य पहल

प्राप्तियाँ

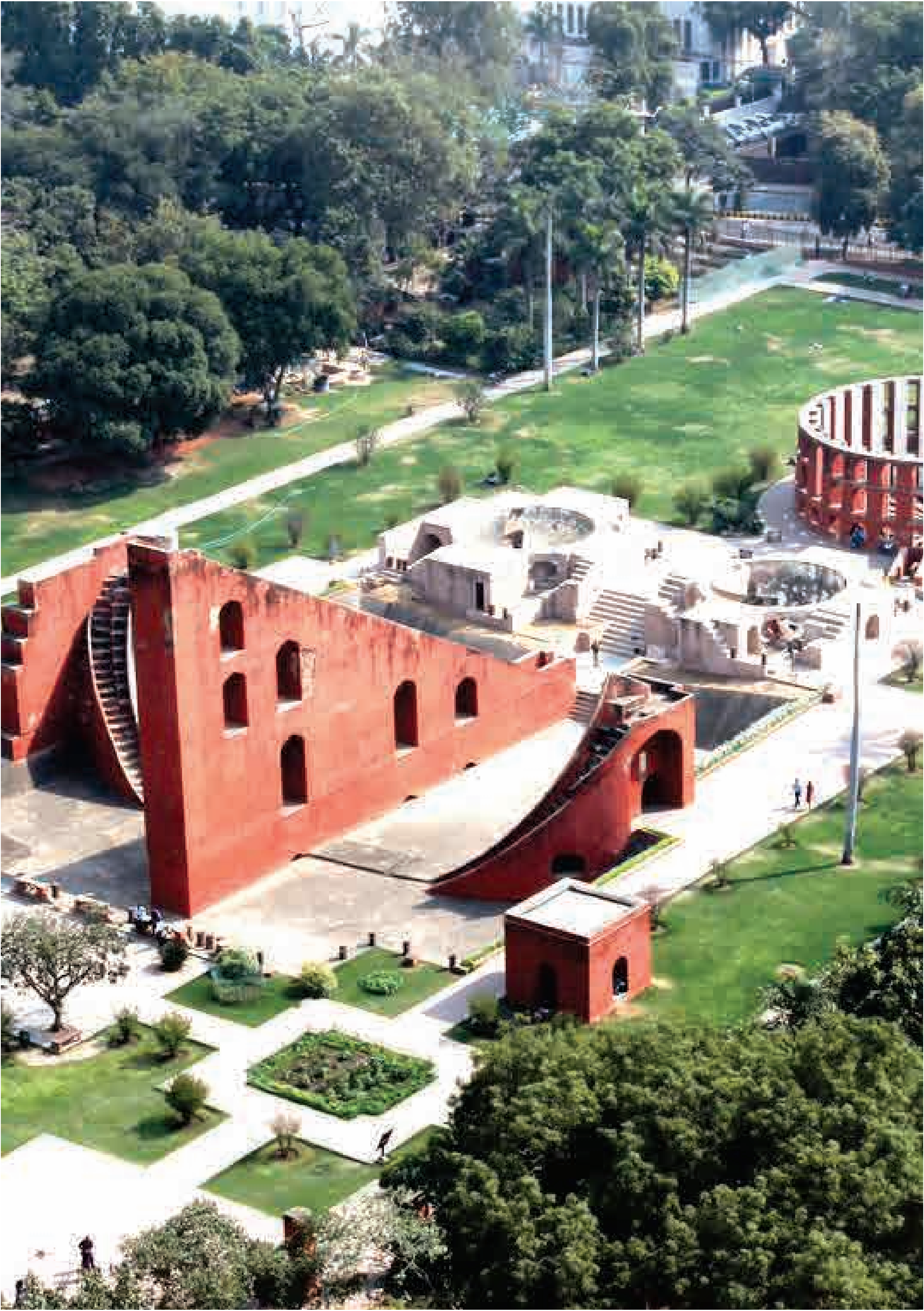

बजट भाषण–2017–18

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के माननीय सदस्यों, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं हमारे संगठन का आगामी वर्ष 2017–18 का बजट प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ।

न.दि.न.परिषद् के इतिहास में पहली बार, बजट को बनाने में परिषद् की वेबसाइट, मोबाइल एनडीएमसी 311 ऐप, इयादि के माध्यम से बजट 2017–18 से नागरिकों की अपेक्षाओं पर उनके सुझावों को आमंत्रित किया गया। प्रतिक्रिया सकारात्मक है, जहाँ बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए तथा उचित रूप से विचार किया गया।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वर्ष 2017–18 स्मार्ट टेक्नॉलाजी के हस्तक्षेप के माध्यम से सुशासन वर्ष होगा। ई–गवर्नेंस तथा एम–गवर्नेंस, सुशासन सुनिश्चित करने के प्रमुख साध्न होंगे। मैं न.दि.न.परिषद् क्षेत्रा को एक रहने योग्य, व्यवहारिक तथा सुखद स्थान बनाना चाहता हूँ। न.दि.न.परिषद् क्षेत्रा को सभी के लिए सुगम बनाने की मेरी अभिलाषा है।

मैं अल्पावधि सुधरों की तलाश करने के लिए नहीं, किन्तु इस बजट के माध्यम से नई दिल्ली के दीर्घावधि व संपूर्ण विकास का लक्ष्य रखना प्रस्तावित करता हूँ।

राजधनी शहर हेतु न.दि.न.परिषद् को वैश्विक प्रतिमान (बेंचमार्क) बनाने के परिषद् के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं वार्षिक बजट 2017–18 को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1 मैं वित्तीय अनुमान पहले प्रस्तुत करना चाहूँगा :

बजट अनुमान 2017–18 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 3627.08 करोड़ की हैं, जबकि संशोध्ति अनुमान 2016–17 में ₹ 3404.51 करोड़ का प्रावधन किया गया है। वर्ष 2015–16 में कुल वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 3351.46 करोड़ थीं। बजट अनुमान 2017–18 में रजस्व प्राप्तियाँ ₹ 3066.35 करोड़ की है जबकि संशोधित अनुमान 2016–17 में ये ₹ 2961.24 करोड़ है, और वर्ष 2015–16 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2920.65 करोड़ की थीं। बजट अनुमान 2017–18 के लिए पूँजीगत प्राप्तियों के ₹ 560.73 करोड़ हैं, जबकि संशोध्ति अनुमान 2016–17 में ये ₹ 443.27 करोड़ हैं और वर्ष 2015–16 में वास्तविक पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹ 430.81 करोड़ की थी।

बजट अनुमान 2017–18 में कुल व्यय ₹ 3621.62 करोड़ है, जबकि संशोधित अनुमान 2016–17 में यह ₹ 3296.25 करोड़ है और वर्ष 2015–16 में वास्तविक व्यय ₹ 2925.78 करोड़ का था। बजट अनुमान वर्ष 2017–18 में राजस्व व्यय के लिए ₹ 3062.07 करोड़ रखे गए हैं जो संशोध्ति अनुमान 2016–17 में ₹ 2958.57 करोड़ है और वर्ष 2015–16 में वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 2868.13 करोड़ था। बजट अनुमान 2017–18 के अनुसार पूँजीगत व्यय ₹ 559.55 करोड़ (जिसमें स्मार्ट परियोजनाओं के लिए ₹ 155.78 करोड़ शामिल है) आंका गया है, जो संशोधित अनुमान 2016–17 में ₹ 337.68 करोड़ (जिसमें स्मार्ट परियोजनाओं के लिए ₹ 13.83 करोड़ शामिल है) है, जबकि वर्ष 2015–16 का वास्तविक पूँजीगत व्यय ₹ 57.65 करोड़ था।

1 स्मार्ट सिटी मिशन

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के प्रथम चरण में 20 शहरों में से नई दिल्ली नगर पालिका का चयन किया गया। चयन के उपरांत, परिषद् तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ न.दि.न.परिषद् ने ”न्यू डेल्ही म्युनिसिपल काउंसिल स्मार्ट सिटी लि॰ (एसपीवी) नाम से एक पूर्ण स्वामित्व पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना की है। एसपीवी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ₹ 194 करोड़ तथा न.दि.न.परिषद् से ₹ 56 करोड़ का अनुदान प्राप्त कर ₹ 250 करोड़ की सीड कैपीटल बन गई। सभी नामित निदेशकों को नियुक्त कर दिया गया है। परिषद् सचिव को एसपीवी के अंतरिम मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। कम्पनी ने अपने संगठन के ज्ञापन तथा संगठन के अनुच्छेद के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया है। पुनः न.दि.न.परिषद् ने एसपीवी को वर्ष 2017–18 में ₹ 50 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 44 करोड़ हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

2 ई–गवर्नेंस, एम–गवर्नेंस तथा जन–साधरण सहभागिता के माध्यम से सुशासन।

2.1 बजट 2017–18, सुशासन सुनिश्चित करने के लिए टैक्नोलॉजी के हस्ताक्षेप द्वारा पारदर्शी पद्धति में निष्पक्षता, दक्षता तथा प्रभावशीलता बढ़ाने की परिकल्पना की गई, जिसमें शामिल है :

2.1.1 डिजाइन द्वारा ओपन न.दि.न.परिषद्

2.1.1.1 वर्ष 2016–17 में, न.दि.न.परिषद् ने मोबाइल एनडीएमसी 311 ऐप द्वारा नागरिकों की सहभागिता पर ध्यान केन्द्रित किया है, जिसके माध्यम से जनसाधरण से निरंतर प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। न.दि.न.परिषद् की न्यू यूजर फ्रेंडली वेबसाइट शुभारंभ की गई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन से जनसाधरण के लिए शार्ट कोड नियंत्रण कक्ष संख्या "1533" प्रारंभ की गई। नागरिक रचनात्मक ढंग से योजनाओं के डिजिटल मीडिया जैसे– "कैप्चरिंग ब्यूटी ऑपफ एनडीएमसी थ्रू लेंसिस", "डिजीटल पोस्टर मेकिंग फॉर स्वच्छ भारत मिशन एण्ड डिजीधन", "पेडेस्ट्रीनाइजेशन ऑफ कनाट प्लेस", क्राउड सोर्सिंग डेंगू अवेयरनेस मूवी, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए फीडबैक इत्यादि, की ओर प्रवृत हुए। नियमित रूप से आवास कल्याण संगठनों के साथ आमने–सामने विचार–विमर्श आयोजित किए गए।

2.1.2 उपभोक्ता अनुभव में सुधर के लिए सार्वजनिक सेवा सुशासन को सशाक्त करना।

2.1.2.1 मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एनडीएमसी 311 ऐप का शुभारंभ हो गया है। जनसाधरण, मामले के प्रकार के चयन द्वारा मोबाइल के माध्यम से अपनी शिकायत कर सकते हैं। एनडीएमसी 311 ऐप, मामले का प्रकार तथा उपभोक्ता की जीपीएस लोकेशन के आधर पर, शिकायत को आगामी कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी का आलेख करता है। एनडीएमसी 311 ऐप की प्रतिक्रिया जोरदार है तथा इस ऐप के माध्यम से दिनांक 08.01.2017 तक 14493 मामले प्राप्त हुए, जिसमें से 14201 मामलों का समाधान किया गया। नागरिक सेवाएँ जैसे नागरिक सेवाओं का भुगतान, ओपीडी पंजीकरण, ऑनलाइन मेडीकल स्टॉक प्रदर्शन ऑनलाइन पानी की गुणवत्ता की जाँच इत्यादि एनडीएमसी 311 सिटिजन ऐप की कुछ विशेषताएँ हैं। पुनः अधिकारियों को ई–चालान जारी करने के लिए मोबाइल ई–चालानिंग द्वारा एनडीएमसी 311 आपफीसर्स ऐप प्रारंभ किया है, जिसमें मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। यह ऐप कोर म्युनिसिपल फंक्शन/फील्ड निरीक्षणों की मोबाइल आधरित निगरानी करने में सक्षम है।

2.1.2.2 आगे, न.दि.न.परिषद् ने सूचना प्रौद्योगिकी आधरित ई–गवर्नेंस प्लेटपफार्म के माध्यम

से बहुविध सेवाएँ प्रारंभ की है, जैसे बिल्डिंग प्लान का ऑनलाइन अनुमोदन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रा को निशुल्क ऑनलाइन जारी करना, बिजली पानी के बिलों हेतु आनलॉइन भुगतान, संपत्ति कर तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं जैसे– येलो फीवर टीकाकरण अपॉइंटमेंट, न.दि.न.परिषद् बारात घर एवं अन्य न.दि.न.परिषद् के इवेंट मैनेजमेंट स्थानों की ऑनलाइन उपलब्ध्ता तथा बुकिंग, ओपीडी पंजीकरण, ऑनलाइन मेडीकल स्टॉक उपलब्ध्ता, ऑनलाइन डिमांड आधरित ई–वेस्ट डिस्पोजल इत्यादि। न.दि.न.परिषद् ने नागरिक सेवाओं को प्रदान करने हेतु मोबाइल प्लेटफार्म में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।

2.1.3 जनसाधरण की सहभागिता

2.1.3.1 किसी भी योजना, परियोजना अथवा विकासत्मक गतिविधि की बेहतर प्रभावशीलता तथा अंगीकरण हेतु जनसाधरण की सहभागिता आवश्यक है, जो विचारों को तैयार करने के स्तर पर जनसाधरण के सुझावों से प्रारंभ, तथा जमीनी स्तर पर इन विचारों के लागू होने पर तथा उनके निष्पादन की प्रतिक्रिया तक होते हैं।

3 स्मार्ट टैक्नोलॉजी

3.1 प्रौद्योगिकी मध्यवर्तन

3.1.1 अत्यध्कि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, दक्षता तथा तत्परता के लिए, वर्ष 2016–17 में ई–गवर्नेंस के अन्तर्गत ऑनलाइन सेवाओं पर विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है। ई–गवर्नेंस प्लेटफार्म में मोबाइल एप्लीकेशन के व्यापक प्रयोग को नागरिकों की शिकायतों के निवारण, फिल्ड निरीक्षण, सेवाएं देने इत्यादि हेतु एप्लीकेशन्स आधरित स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से परिकल्पित किया गया था।

3.1.2 चल रहे कार्यों में उसके उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रभाविकता के सुधर के लिए जनसाधरण को सम्मिलित कर, यह न.दि.न.परिषद् में चल रही तथा लम्बित परियोजनाओं के लिए एप्लीकेशन को सृजित करना प्रस्तावित किया जाता है जिससे जन साधरण इन परियोजनाओं की आसानी से समीक्षा करें कि इससे उनका जीवन प्रभावित होता है।

3.1.3 आगे न.दि.न.परिषद् का प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन पोर्टल प्रारंभ करना प्रस्तावित किया जाता है जहाँ जनसाधरण नागरिक सेवाओं के सुधर के लिए नये सुझावों तथा समाधनों को प्रस्तुत करें। यह कदम नागरिक सेवाओं के लिए पहुँच में सुविधा बढ़ाने के लिए तथा सार्वजनिक संसाधनों के अनुकूलन में मदद करने के लिए नये तकनीकी योजनाओं को लाना होगा।

3.1.4 वर्ष 2017–18 में सार्वजनिक पारस्परिकता बढ़ाने के लिए जनसाधरण को उनके विचार तथा सुझावों को देकर नागरिकों तथा आगंतुकों को प्रोत्साहित करने के लिए डेशबोर्ड का विकास करना प्रस्तावित किया जाता है। इस डेशबोर्ड में विशेषताए जैसे चिन्हित मानदण्डों इत्यादि के बदले अन्य राष्ट्रीय तथा अन्र्तराष्ट्रीय शहरों के साथ स्थापित लक्ष्यों, बेंचमार्किंग के संबंध में निष्पादन की तुलना होगी।

3.1.5 सोशल मिडिया के माध्यम से न.दि.न.परिषद् की योजनाओं, परियोजनाओं तथा पहलों के बारे में जनसाधरण को जागरूकता बढ़ाने के लिए, विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन चर्चा, पोल्स, सीध प्रसारण प्रश्नावली (लाइव क्वेश्चन) तथा उत्तर सत्र, सर्वेक्षण तथा विचार विमर्श पोस्ट करना पारित किया जाता है।

ऐसे सोशल मिडिया के माध्यम से फिडबैक न.दि.न.परिषद् की सेवाओं तथा ब्रिज गेप यदि कोई है, को सुधने के आवश्यकत निर्णय लेने के लिए निगरानी रखी जाएगी।

3.2 डिजिटल इन्टरएक्टिव सूचना (इनपफोर्मेशन) पैनल

स्मार्ट डिजिटल इन्टरएक्टिव सूचना पैनलों से न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आनलाइन सूचना का सीधा प्रसारण न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में करना पारित किया जाता है। जोकि वाई–फाई हॉटस्पॉट के रूप में काम करेगा। ये डिजिटल इन्टरएक्टिव सूचना पैनल न.दि.न.परिषद् क्षेत्र को अधिक जीवंत और उत्तरदायी बनायेंगे।

3.3 भारत सरकार के उपक्रम एमटीएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन करना पारित किया जाता है जोकि सार्वजनिक स्थलों पर हायर स्पीड पर वाई–फाई सेवाओं जैसे बेहतर वायरलैस कम्यूनिकेशन प्रदान करने के नेटवर्क में निवेश हैं यह एक पारदर्शी, समय तथा लागत की बचत पद्धति में ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को पहुँचाने में उपयोगकर्ताओं को सक्षम करने के लिए आवश्यक है। इस संबंध में न.दि.न.परिषद् की एसपीवी ने मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) एमटीएनएल की 100 प्रतिशत सहायक है जो इसके निवासियों को एपफटीटीएच (फाइबर टू द होम) प्रदान करने के लिए न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में एक दूरसंचार नेटवर्क पहुँच नेटवर्क विकसित करना है, के साथ 50:50 का एक ज्वाइंट वेन्चर सृजित करना प्रस्तावित किया जा रहा है। वाई–फाई सेवाएं समुच्चय स्विचों के माध्यम से एम पी एल एक पर सीधे अथवा एपफटीटीएच बैकबोन पर चला सकते हैं।

3.4 डाटा सेंटर के साथ कमाण्ड तथा नियंत्राण केन्द्र

न.दि.न.परिषद् की बहुत सी नागरिक प्रशासन की गतिविधियाँ अब आईटी सपोर्ट/समाधनों के माध्यम से निष्पादित की जाती है। जिसका लगातार निवासियों तथा आगंतुकों के लिए कई उपकरणों के माध्यम से विस्तार कर रहे हैं। न.दि.न.परिषद् आईटी/आईसीटी आधरित हस्तक्षेप तथा समाधनों के प्रयोग के साथ न.दि.न. परिषद् को एक स्मार्ट सिटी में विकसित करने की पहले से ही प्रक्रिया में है। अभिगम नियंत्राण तथा विशेषाधिकार प्रतिबंधें की एक उच्च डिग्री प्रदान करते समय सचालनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता देने के लिए, न.दि.न.परिषद् हेतु डाटा सेंटर के साथ एक पूर्ण विकसित कमांड तथा नियंत्रण केन्द्र होना प्रस्तावित किया जाता है। इसके लिए बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 20 करोड़ का बजट प्रावधन रखा गया है।

3.5 प्वाइंट्स ऑपफ डिलीवरी के रूप में कार्य करने के लिए रिमोट सूचना क्योस्क

समस्त परिचालन लगातों को कम करते हुए नागरिकों सुदूर उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान कर न.दि.न.परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई बड़ी संख्या में ई–गवर्नेंस नागरिक सेवाओं के लिए नागरिकों तथा न.दि.न.परिषद् के बीच सहभागिता परिवर्तन के लिए, 5 स्थानों पर रिमोट सूचना बूथ बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जोकि प्वाइंट्स आपफ डिलीवरी के रूप में काम करेंगे। लम्बी अवधि हेतु अधिक सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु सेवाओं के प्वांइटों को नागरिकों के पास लाते हुए वर्तमान आई टी संघटकों के साथ, इसकी पहुँच न.दि.न.परिषद् को आधुनिकीकृत करने में सहायता करना उद्दिष्ट हैं। यह समाधन नागरिकों को केन्द्र/राज्य सरकार तथा अन्य ई–सेवाओं, न.दि.न.परिषद् तक शीघ्र तथा सरल पहुँच के साथ उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधरने में सहायता करेगा।

3.6 सम्पत्तियों/संस्थानों हेतु स्मार्ट एड्रेसिंग समाधन

न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में सम्पत्तियों/संस्थानों हेतु एक अनूठा स्मार्ट एड्रेसिंग समाधन विकसित करना प्रस्तावित हैं। यह समाधन न केवल नंबर योजना द्वारा अपितु जिओ–लोकेशन (भू–स्थान) को अनुमति देते हुए जी आई एस आधरित नक्शे में इस नंबर योजना को भी प्रस्तुत करते हुए सहज रूप से जाना जाएगा तथा नेविगेशन सेवाओं को भी प्रभावी ढंग से प्रदान

किया जाएगा। यह नागरिक सेवाओं की योजना बनाने में बहुत दूर तक जाएगा।

3.7 न.दि.न.परिषद् प्रौद्योगिकी बोर्ड

न.दि.न.परिषद् को रहने, कार्य करने तथा आनंद हेतु बेहतर स्थान बनाने हेतु अधिक दक्षता तथा प्रभाविकता लाने हेतु टेक्नोलॉजी नवप्रवर्तन को आगे बढ़ाने हेतु शिक्षा, अनुसंधन संस्थानों, कंपनियों तथा अन्य इसी प्रकार के संस्थापित संस्थानों से मेनटॉर लेते हुए न.दि.न. परिषद् प्रौद्योगिकी बोर्ड को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

3.8 इनक्यूबेशन सेंटर

3.8.1 न.दि.न.परिषद् ने इलैक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, के अंतर्गत सॉफ्रटवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, एक स्वायत सोसाइटी के साथ इन्कयूबेशन सेन्टर आरंभ करना प्रस्तावित किया है। न.दि.न.परिषद् 20 नई स्टार्ट–अप कंपनियों को इनक्यूबेटिंग करने हेतु अध्कितम 10,000 वर्ग पफीट क्षेत्र निर्मित करना होगा।

3.8.2 एसटीपीआई के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की औपचारिकताएं चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में, पूर्ण होने की संभावना होगी तथा इन्क्यूवेशन सेंटर वर्ष 2017–18 में कार्य करना आरंभ करेगा। इस उद्देश्य हेतु बजट–अनुमान 2017–18 में ₹ 5 करोड़ का बजट प्रावधन रखा गया है।

3.8.3 डिजिटल प्रशिक्षुता

मैं डिजिटल स्टार्ट–अप/वैयक्तिकों के चयन हेतु 4 डिजिटल प्रशिक्षुताओं को आरंभ करना प्रस्तावित करता हूँ जोकि नेशनल लेवल हेक्थान द्वारा एक वर्ष की अवधि हेतु चुना जाएगा। भागीदार वैयक्तिक/टीमों न.दि.न. परिषद् द्वारा सामना की जा रही वास्तविक समय की चुनौतियों का समाधन करने हेतु डिजिटल अभी तक सतत् अभिनव समाधन की पेशकश के लिए एक ही समय में प्रतिस्पर्धा की जाएगी। यह उज्जवल युवा मन के लाखों लोगों की रचनात्मकता को उपयोग में लाएगा, तथा यह न केवल डिजिटल प्रशिक्षुओं के रूप में राष्ट्रीय प्रतिमा को बढ़ावा देगा अपितु टेक्नोलॉजिकल विचारों की संभाव्यता तथा कार्यान्वयन को बनाने हेतु समाधन उपलब्ध कराना आशायित है। इन 4 प्रशिक्षुताओं को कुल ₹ 50 लाख प्रदान किए जाएंगे।

3.9 प्रौद्योगिकी नवप्रर्वतन फंड

इन स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल पहल के लिए मैं ₹ 7.5 करोड़ की निधि का सृजन करना प्रस्तावित करता हूँ, जिसका आगे नागरिकों को सुविध देने हेतु नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी योजनाओं/परियोजनाओं को बढ़ाने हेतु उपयोग किया जाएगा।

3.10 स्ट्रीट लाइट खंभे

3.10.1. पहले भी न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत वार्म एलईडी फीटिंग्स के साथ सभी स्ट्रीट लाइट खंभों को बदलना प्रस्तावित किया गया था। दोबार आरएफपी चलायमान करने के बावजूद, इंडस्ट्री से कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं आया।

3.10.2 तद्नुसार, चन्द्रगुप्त मार्ग हेतु वार्म एलईडी के साथ सोडियम वाष्प लाइटों/सीएफएलों को बदलने हेतु पायलट परियोजना हेतु आरएपफपी चलायमान की गई, जिसके लिए बोलियां प्राप्त की गई तथा कार्य जनवरी 2017 को परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् सपफल बोलीदाताओं को सौंपा जाएगा। काका नगर आवासीय कालोनी हेतु अन्य पायलट परियोजना आरएपफपी चलायमान की गई, तथा जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्य सौंपे जाने की संभावना है। इन दो पायलट परियोजनाओं के निष्कर्षों के आधर पर, वर्ष 2017–18 में वार्म एलईडी लाइटों के साथ सभी स्ट्रीट लाइटों को बदलने हेतु कार्रवाई की जाएगी। इस उद्देश्य हेतु बजट–अनुमान 2017–18 में ₹ 30 करोड़ का प्रावधन रखा गया है।

3.10.3 आगे, कनॉट–प्लेस तथा सड़कों को जोड़ने के लिए 55 स्मार्ट पोलों हेतु पायलट परियोजना पीपीपी मॉडल के अंतर्गत चलायमान की गई जिसमें वर्तमान विद्युत के खम्भों को सीसीटीवी कैमरों, वार्म एलईडी, पर्यावरणीय सेंसरों तथा वाई–फाई की विशेषताओं वाले स्मार्ट पोलों के साथ बदला जाएगा।

3.11 वृहद् आकार की मल्टी मीडिया एलईडी स्क्रीन

तीन 20x10 पफीट मल्टी मीडिया एलईडी स्क्रीनों हेतु कार्य सौंपा जा रहा हैं, जोकि मार्च 2017 में पूर्ण होने की संभावना हैं। इन स्क्रीनों का राजस्व अर्जन हेतु विज्ञापन उद्देश्य सहित वास्तविक समय वायु–गुणवत्ता निगरानी डाटा के प्रसार हेतु प्रयोग किया जाएगा।

3.12 चूँकि न.दि.न.परिषद् टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भर हो रही है, इसलिए, अधिक बजट की सहायता देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सशक्त करने की आवश्यकता हैं। ऐसी सभी पहलों का मार्गदर्शन करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त पदों का सृजन करना प्रस्तावित है।

3.13 न.दि.न.परिषद् का हरित भविष्य उद्यमी पारितोषित

विद्यार्थियों के लिए न.दि.न.परिषद् के हरित भविष्य उद्यमी पारितोषित (स्वर्ण, रजत तथा कांस्य) में ₹ 5 लाख, ₹ 3 लाख तथा ₹ 1 लाख क्रमशः प्रतिवर्ष शुरू करना प्रस्तावित किया जाता है जोकि विद्यार्थियों के बीच वायु गुणवत्ता, जल उफर्जा, नगरपालिका कूड़ा, शिक्षा, चिकित्सा सेवाएँ, परिवहन इत्यादि के लिए प्रोत्साहित करने की अभिनव सोच है। ऐसे विद्यार्थियों के चयन हेतु मौलिकता, व्यवहारिकता तथा कार्बन सेविंग मानदण्ड है।

4 न.दि.न.परिषद् की शहर सरंचना

4.1 विद्युत

4.1.1 वर्ष 2016–17 ने पीक लोड, नवीकरण उफर्जा एकीकरण, परिचालन दक्षता में सुधर जिससे एटी एवं सी घाटा तथा उपभोक्ता सेवाओं के प्रबंधन के लिए स्मार्ट इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ 11 केवीए नेटवर्क, स्काडा समर्थकारी, 100 प्रतिशत स्वचलित मीटरिंग संरचना के साथ स्वचलित मांग प्रतिक्रिया, पिफल्ड पफोर्स स्वचालन, सब–स्टेशन स्वचालन, स्मार्ट मीटरों तथा ग्रिड प्रबंधन के लिए नेटवर्क, नेट मिटरिंग इत्यादि जैसी विशेषताओं को तीन वर्ष के कार्यन्वयन अवधि के साथ न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया था। आगे पावर मंत्रालय, भारत सरकार ने ₹ 196.92 करोड़ के अनुमोदित डीपीआर के बदले आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत ₹ 119.13 करोड़ के अंशदान का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन दे दिया। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि न.दि.न.परिषद् ने एक परामर्शदाता चयन किया गया है जो ई.डी.एफ. जोकि फ्रांस सरकार की इकाई है और डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. भारत सरकार का मिनी रत्न उपक्रम है इन दो संस्थाओं का संयुक्त संकाय है।

4.1.2 तकनीकी विशिष्टताओं तथा मात्रा का बिल (बीओक्यू) को विद्युत वितरण नेटवर्क के सशक्तिकरण के लिए अन्तिम रूप दिया गया है तथा उक्त हेतु निविदा को शीघ्र ही आमंत्रित किया जाएगा। स्काडा समर्थकारी हेतु तकनीकी विशिष्टताओं तथा मात्रा का बिल (बीओक्यू) को अन्तिम रूप देना तथा 100 प्रतिशत स्वचलित मीटरींग संरचना के साथ स्वचलित मांग प्रतिक्रिया के भी इस वित्तीय वर्ष के निविदाएँ कार्य सौंपने के लिए सुविधग्राहियों के चयन हेतु जारी किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 25 करोड़ का बजट प्रावधन रखा गया है तथा इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में भारत से ₹ 35.74 करोड़ की राशि की आशा है।

4.1.3 सौर ऊर्जा

4.1.3.1 मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि न.दि.न.परिषद् देश में कुछ बिजली वितरक इकाईयों में से एक तथा केवल दिल्ली में एकमेव है जोकि भारत सरकार द्वारा बनाए गए मानकों के अनुसार हरित ऊर्जा की खरीद द्वारा अपने नवीकरण पावर दायित्वों को पूरा कर रहा है।

4.1.3.2 सौर ऊर्जा के क्षेत्र में न.दि.न.परिषद् के कई कदम उठाए हैं। न.दि.न.परिषद् इस क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है तथा वर्ष 2016–17 में 63 भवनों में 3.5 एम डब्ल्यू रूफ टॉप सौर पैनलों को चालू किया गया है। आगे 74 भवनों में 0.9 एम डब्ल्यू परियोजनाएँ चल रही हैं जोकि वर्ष 2016–17 में चालू की जाएंगी।

4.1.3.3 न.दि.न.परिषद् राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्रा दिल्ली सरकार के साथ वर्ष 2016–17 में वर्णित 10 एमडब्ल्यू सौर पावर संयंत्र के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। तथापि, परिषद् ने आरईडब्ल्यूए में स्थित मध्यप्रदेश के सरकारी सौर संयंत्र तथा ₹ 4.75 प्रति केडब्ल्यूएच की दर पर राजस्थान से भारतीय सौर ऊर्जा निगम से 25 वर्षों के लिए 50 एमडब्ल्यू पावर की खरीद हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया। प्राप्त की गई दरें बहुत प्रतिस्पर्धी है इसलिए दीर्घ अवधि करार के अन्तर्गत इन राज्य सरकारों से सौर ऊर्जा की खरीद के साथ–साथ न.दि.न.परिषद् द्वारा सौर संयंत्र के गठन की वित्तीय सभांव्यंता वियमान नहीं होती है। खरीद के ऐसे प्रबंधन का न.दि.न.परिषद् के प्ररूपी लोड प्रोफाइल के साल मिलान होगा अर्थात् रात्रि के दौरान असामान्य रूप

से कम मांग तथा दिन के समय अधिक मांग है। सौर शक्ति के समय अधिकतम तथा रात्रि के दौरान शून्य भी उपलब्ध होगी।

4.1.3.4 न.दि.न.परिषद् मुख्यालय भवन को जहां तक संभव हो हरित भवन बनाने के लिए, न.दि.न.परिषद् भवनों जैसे पालिका केन्द्र अग्रभाग सौर पैनलों की स्थापना करना प्रस्तावित किया जाता है। आगे यह प्रस्तावित किया जाता है मोती बाग, नई दिल्ली में कौशल दक्षता केन्द्र भवन में रूफ–टॉप सौर पैनल तथा अग्रभाग के लिए आवश्यक प्रावधन किए जाएंगे।

4.1.3.5 चूंकि न.दि.न.परिषद् के परिसरों का रूफ–टॉप स्थल सीमित है तथा लगभग पता लगाया जाता है रूफ–टॉप संस्थापनाओं पर भारत सरकार की 30 प्रतिशत पूंजी सहायता योजना की सुविध द्वारा न.दि.नपरिषद् क्षेत्र में निजी भवनों पर रूफ–टॉप सौर को बढ़ावा देने अब प्रस्तावित किया जाता है। भारतीय सौर निगम (एसईसीआई) ने निजी व्यक्तियों को पूंजी सहायता बढ़ाने के लिए विक्रेताओं तथा दरों को अंतिम रूप दिया गया है। न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में निजी भवनों पर सौर रूफ–टॉप पैनलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पूँजी सहायता संवितरण की सुविध एसईसीआई तथा निजी व्यक्तियों के बीच न.दि.न.परिषद् एक प्रणाली जोड़ने का काम करेगी।

4.1.4 बिजली बचाने के लिए, न.दि.न.परिषद् भवनों में सभी विद्यमान लाइटों को विद्युत संरक्षण के लिए एलईडी लाइटों में परिवर्तित किया गया है।

4.1.5 प्रेजिडेंट एस्टेट तथा राष्ट्रपति भवन को एचटी कनैक्शन प्रदान करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रेजिडेंट सेकरेटेरियट, जी प्वाइंट के कर्मचारियों के लिए टाइप–II तथा III बहुमंजिलों आवासीय क्वार्टरों के लिए विद्युत कनैक्शन प्रदान करने का कार्य पूर्ण हो गया है।

4.1.6 न.दि.न.परिषद् के स्काडा पर सभी 33 तथा 66 के वी ग्रिड सब–स्टेशनों की डाटा कनैक्टिविटी तथा निर्माण भवन नियंत्राण कक्ष पर डीटीएल की स्काडा प्रणाली का एकीकरण पूर्ण हो गया है।

4.1.7 विद्युत सब–स्टेशन हरीश चन्द्र माथुर लेन पर नए ट्रांसपफार्मरों के साथ दो पुराने 33/11 के वी 16 एमवीए पावर ट्रांसपफार्मरों को बदलना तथा वर्ष 2017–18 में विद्युत भवन विद्युत सब–स्टेशन पर पुराने 66/11 के वी 16 एमवीए को बदलना प्रस्तावित किया जाता है। आगे, सिंधिया हॉउस तथा बापू धम पर विद्युत सब–स्टेशन पर 33 के वी स्विच गियर पैनल बोर्ड वर्ष 2017–18 में बदले जाने प्रस्तावित हैं। वर्ष 2017–18 में सफदरजंग अस्पताल पर 33 केवी विद्युत सब–स्टेशन भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं। आगे, वर्ष 2017–18 में चरक पालिका अस्पताल, मोती बाग पर 1x990 के वीएयूएसएस का संस्थापन किया जाएगा।

4.1.8 एक पृथक "स्ट्रेटिजिक बिजनस यूनिट (एसबीयू) फॉर इलैक्ट्रिसिटी" के गठन हेतु नियुक्त मैं॰ एसबीआईसीएपीएस, द्वारा की गई प्रमुख अनुशंसाएं स्वीकार की गई तथा कार्यान्वयन किया जा रहा हैं तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 से शुरू हो जाएगा।

4.1.9 बजट अनुमान 2017–18 में विद्युत विभाग हेतु ₹ 1284.94 करोड़ का प्रावधन रखा गया हैं जिसमें से पूंजीगत व्यय हेतु ₹ 122.95 करोड़ हैं।

4.2 जल प्रबन्ध्न

4.2.1 इसके निवासिों को 24x7 गुणवत्ता तथा विश्वसनीय जल की आपूर्ति देने के लिए तथा देश के अन्य भागों में की गई ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुए अनुभव के आधर पर,

यह प्रस्तावित किया जाता हैं कि परियोजना दो स्तरों पर कार्यान्वित की जाएगी। प्रथम स्तर में कार्य जैसे मामूली संशोधनों, जल मीटरों को लगाना, जल ऑडिट, कुटुम्ब आपूर्ति कनैक्शनों (एचएससीज़) के प्रतिस्थापन, जल गुणवत्ता सेंसरों के संस्थापन, कलोरीनीकरण का पता लगाने, एडवांस मीटरिंग इंप्रफास्ट्रक्चर (एएमआइ) मीटर, अनिवार्य जीआईएस नक्शों का सृजन, इत्यादि के साथ विद्यमान नेटवर्कों पर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग एरिया (डीएमएज़) के सृजन सम्मिलित होंगे। द्वितीय स्तर में पुर्नस्थापन, प्रतिस्थापन तथा जल बूस्टिंग पम्प स्टेशनों के साथ जलापूर्ति नेटवर्क का उन्नयन प्रथम स्तर की परियोजनाओं के परिणामों के आधर पर किया जाएगा। इस संबंध में बजट-अनुमान 2017-18 में ₹ 20 करोड़ का प्रावधन रखा गया है।

4.2.2 न.दि.न.परिषद् ने बंगाली मार्किट में तथा सफदरजंग लेन में क्रमशः ₹ 1.48 करोड़ तथा ₹ 0.95 करोड़ की लागत पर पुरानी पाइप लाइनें बदली है जिसके कारण इन क्षेत्रों में जलापूर्ति में सुधर आया है। 10 वाटर टेंकर स्टेनलैस स्टील के बने हैं, क्रय किए गए तथा संचालन में हैं। वर्ष 2017–18 में, पिलंजी गाँव में पुरानी सी आई लाइनों को बदलने का चालू कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित हैं। 800 मि.मी. एच.एस. जल लाइन मोती बाग, सान मार्टिन मार्ग में स्थांतरित की जानी प्रस्तावित है। पंडारा रोड में जलापूर्ति नेटवर्क का सुधर किया जाना है, जहां कार्य जनवरी 2017 के अंत तक होने की संभावना है।

4.2.3 बजट अनुमान 2017–18 में जलापूर्ति कार्य हेतु 165.85 करोड़ का प्रावधन रखा गया है जिसमें से पूंजीगत व्यय हेतु 29.81 करोड़ है।

4.3 सीवर प्रबंध्न

4.3.1 आगंतुकों के लिए न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में गुणवत्ता पेयजल उपलब्ध कराने हेतु (पीपीपी) सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में जल एटीएम स्थापित करना प्रस्तावित किया गया। तत्पश्चात्, परिषद् ने जल को प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में मानते हुए इन जल एटीएमों का निर्माण करने का निर्णय लिया। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में 15 जल एटीएमों के संस्थापन हेतु बोलियां प्राप्त की गई तथा कार्य शीघ्र ही सौंपा जाएगा। वर्ष 2017–18 में न.दि.न.परिषद् के अन्य क्षेत्रों में जल एटीएमों की संख्या बढ़ाया जाना प्रस्तावित हैं। इस संबंध में बजट अनुमान वर्ष 2017–18 में ₹ 1 करोड़ का प्रावधन किया गया है।

4.3.2 पूर्वी किदवई नगर में सीवर लाइन के स्थानांतरण का कार्य पूर्ण हो गया है। पिलंजी गाँव में विद्यमान सर्विस रोड तथा निकास पद्धति, सीवरेज पद्धति तथा जलापूर्ति का सुधर कार्य जून 2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित हैं।

4.3.3 तालकटोरा गार्डन में तृतीयक उपचार संयत्र का निर्माण तथा भारती नगर में 50 केएलडी एसटीपी का संस्थापन पूर्ण हो गया, इनसे प्राप्त उपचारित जल उद्यानों में प्रयोग किया जा रहा है।

4.3.4 न.दि.न.परिषद् ने 0.93 एमलडी की कुल क्षमता के एसडीपी आधरित 12 फाइटोराइड् के कार्यान्वयन हेतु नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च संेटर (एईईआरआई) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। न.दि.न.परिषद् द्वारा ऐसा एक एसटीपी के संस्थापन हेतु निविदा जारी की गई जिसके लिए दो बोलियाँ प्राप्त की गई। वर्ष 2017–18 में न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में एसटीपी आधरित इन 12 फाइटोराइड़ को संस्थापित करना प्रस्तावित है, जिसके लिए

बजट अनुमान वर्ष 2017–18 में ₹ 1.33 करोड़ का प्रावधन किया गया है। वर्ष 2017–18 में न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में 200 मीटर तक फैले हुए कुशक नाले की सफाई भी की जाएगी। इन एसटीपी से उपचारित जल बागबानी हेतु तथा न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में मुख्य सड़कों पर वृक्षों की धुलाई के लिए प्रयोग किया जाएगा।

4.3.5 न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में 3.1 एमएलडी की कुल क्षमता के 10 मि.मी. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) संस्थापित करना प्रस्तावित किया गया। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कार्य इन 10 एसटीपीज़ मॉडल के अंतर्गत कार्य सौंपा गया, जिसमें से दो, जनवरी, 2017 के अंत तक, तीन, फरवरी 2017 तक, एक मार्च 2017 तक, तथा शेष जून 2017 तक चालू किए जाने की संभावना है। इस संबंध में बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 3 करोड़ का प्रावधन किया गया।

4.3.6 सीवर में निवारक रखरखाव उपायों की प्रभावशीलता हेतु सात वर्षों की अवधि के लिए 28 करोड़ की लागत पर जेंटिग सुविध के साथ दो सक्शन–कम–रीसाइक्लर मशीनों को किराए पर लेने के लिए कार्य सौंपा गया।

4.3.7 सीवर/सीवरेज ट्रीटमेंट कार्यों हेतु बजट अनुमान वर्ष 2017–18 में ₹ 99.82 करोड़ का प्रावधन रखा गया, जिसमें से पूंजीगत व्यय हेतु ₹ 10.14 करोड़ है।

4.4 स्मार्ट सड़कें

4.4.1 नागरिकों तथा पैदलयात्रियों की सुविध के लिए स्मार्ट सड़के, आज के समय की आवश्यकता है। मोटरचलित, पैदलयात्रियों तथा नॉन–मोटोराइज्ड वाहन ट्रैफिक के लिए चिकनी तथा सुरक्षित आवाजाही हेतु साइकिल ट्रैक, बेहतर भूदृश्यावली, स्ट्रीट फर्नीचर, प्लाजा–इएटेरीज, पेलीलेन क्रांसिग, 3डी जेबरा क्रांसिग, पांर्किंग, संकेतकें – रोड मार्किंग, बस–स्टैण्डों, भूदृश्यावली प्रकाश, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक शौचालयों पेय जल सुविधओं सहित विशेषताओं के साथ सड़कों को स्मार्ट सड़कों में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रथम चरण में वर्ष 2017–18 में 35 किलोमीटर एवेन्यू सड़कों को लिया जाएगा, जिसके लिए बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 20 करोड़ का प्रावधन रखा गया है।

4.2.2 मुख्य सड़कों पर थर्मोप्लास्टिक पेंट के साथ 24 स्थानों पर 3 डी पेटिंग के लिए कार्य चालू वित्त वर्ष में किया जाएगा।

4.4.3 हॉट मिक्स तकनीक के साथ बी.के. दत्त कालोनी, अलीगंज कालोनी, जोर बाग सड़कों के पुनः सतहीकरण तथा पंडारा रोड, रविन्द्र नगर, सी–हेक्सागन तथा इण्डिया गेट का कार्य पूर्ण हो गया है। सीआरआरआई की अनुशंसाओं के अनुसार हॉट एंड कोल्ड मिक्स तकनीक द्वारा 25 सड़कों में से 9 सड़कों के पुनः सतहीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा वर्ष 2017–18 में पूर्ण हो जाएगा।

4.4.4 परिवर्तित भूमिगत मार्ग

ई– बैंकिग सुविधओं के गठन हेतु टोकन पफीस पर सार्वजनिक क्षेत्रा के बैंकों को प्रस्तावित कर कनाट–प्लेस क्षेत्र में सभी भूमिगत मार्गों में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने की योजना थी, मगर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से इस प्रस्ताव पर खराब प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इसलिए, 5 भूमिगत मार्गों में ब्रांडिग तथा विज्ञापनों के अधिकार द्वारा सब–वे को जीवंत बनाने के लिए

आरएफपी जारी की गई। वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व सुविधग्राही का चयन किए जाने की संभावना है। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर आउटर सर्किल क्रांसिग पर शेष एक भूमिगत मार्गों को केवीआईसी को देने की, योजना है, जो इसे अपनी गतिविधियों के प्रदर्शन द्वारा जीवंत रखेगा जैसा कि इस जक्शंन के प्रदर्शन द्वारा जीवंत रखेगा जैसा कि इस जक्शंन प्वाइंट पर विशाल स्मारकीय चरखा स्थापित किया गया है।

4.4.5 अवरोध रहित एनडीएमसी

विकलांग व्यक्तिों के लिए व्यापक सुलभता प्राप्त करने हेतु न.दि.न.परिषद् की सभी प्रमुख बिल्डिंग, बाजार तथा एवेन्यू सड़के, वर्ष 2017–18 में "डिपार्टमेंट ऑपफ एम्पावंरमेंट विद डिसेबिलिटीज़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुसार "समग्रता एवं सुलभता सूची" के साथ अनुपालन करेगी।

4.4.6 सड़क सुरक्षा

4.4.6.1 दो पर्यटन स्थलों – इण्डिया गेट (राजपथ तथा इण्डिया गेट सर्किल) तथा जंतर–मंतर (संसद मार्ग तथा टॉलस्टाय मार्ग) तथा परिषद् क्षेत्र में सभी बड़े मैट्रों स्टेशनों के निकट सेफ्टी पिन द्वारा सुरक्षा ऑडिट किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा में सुधर की आडिट रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है।

4.4.7 पब्लिक बाइक शेयरिंग

पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत साइकिलों को बढ़ावा देना प्रस्तावित किया गया है। स्मार्ट सड़कों को बना कर सड़क संरचना में सुधर करते समय तथा मोटरचलित/गैर–मोटरचलित परिवहन की प्रभावशीलता, शेयरिंग आधर पर सिटी बाइक से अंतिम छोर तक कनैक्टिवटी होगी जिसमे स्मार्ट पार्किंग समाधन में सुधर आएगा। पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत लगभग 30 शेयर्ड बाइक स्टेशनों को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 500 बाइकें होगी तथा 25 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी।

4.4.8 इलैक्ट्रिकल वाहन

कनाट प्लेस के पेडेस्ट्रनाइजेशन प्रक्रिया के भाग के रूप में पार्क एंड राइड योजना के अन्तर्गत इलैक्ट्रिक वाहनों को न.दि.न.परिषद् में आरंभ किया जाएगा।

4.4.9 सड़क व पटरी शीर्ष के अंतर्गत ₹ 125.70 करोड़ का बजट अनुमान 2017–18 में प्रावधन रखा गया है। जिन में ₹ 27.93 करोड़ पूँजीगत व्यय है।

4.5 स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय यूनिट

न.दि.न.परिषद् क्षेत्र बैंक एटीएम, पेयजल एटीमए, छः नान–इनवौसिव बॉडी बेसिक वाइटल टेंस्टिग (ईसीजी, स्पिरोमेटरी, ऑक्सीमेट्री, ब्लडप्रेशन, ग्लूकोज टैस्ट, बॉडी टैम्परेचर), वेंस्डिग मशीन, हाई क्वालिटी फिंटिग एंड फैसिलिटी जैसे – सैनिटरी नेपकिन वेन्डिग मशीन, सोलर रूफ–टॉप पैनल, जहां संभव हो, जैसी विशेषताओं के साथ 109 स्मार्ट सार्वजनिक हाइज़ीन सेन्टर सहित 149 सार्वजनिक शौचालय यूनिटों का निर्माण कर रहा है। यह पहली बार है, न सिर्फ भारत में किन्तु वैश्विय स्तर पर कि सार्वजनिक शौचालयों में यह सभी सुविधाएँ विकसित

की गई है। यह शौचालय जो पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत बनाए गए हैं, स्वंय धरणीय है तथा यह न.दि.न. परिषद् के लिए राजस्व भी सृजित कर रहे हैं, 10 स्मार्ट सार्वजनिक हाइजीन सेंटर्स सहित 40 सार्वजनिक शौचालय यूनिटों (पीटीयूएस) पूर्ण हो गई है तथा मार्च, 2017 तक 25 और पीटीयू के पूर्ण होने की संभावना है। वर्ष 2017–18 में शेष पीटीयू के पूर्ण होने भी प्रस्ताव है।

4.6 स्मार्ट सेंसर आधरित पार्किंग प्रबंधन पद्धति

न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में 21वीं सदी पर आधरित स्मार्ट पार्किंग साधन पर आधरित पार्किंग की आवश्यकता हैं। तद्नुसार, पीपीपी मॉडल के अंतर्गत मोबाइल एप् के द्वारा ऑनलाइन बुकिंग विशेषताएँ तथा पार्किंग स्थलों की उपलब्ध्ता को वास्तविक समय में बढ़ाने के साथ सेंसर आधरित केन्द्रीकृत स्मार्ट पार्किंग सॉलयूशन उपलब्ध कराने हेतु सुविधाभोगियों के चयन हेतु आरएफपी जारी की गई और बोलियां प्राप्त की गई। कार्य चालू वित्तीय वर्ष में कार्य सौंपा जाएगा। यह संभावित किया गया कि यद्यपि प्रस्तावित साधन नागरिकों को तत्काल राहत देगा तथा पार्किंग स्थलों के द्वारा काफी मात्रा में न.दि.न.परिषद् के राजस्व अर्जन में वृद्धि होगी।

4.7. वाणिज्यिक विकास परियोजनाएँ

4.7.1 एकीकृत ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बुनियादी ढाँचा – शिवाजी टर्मिनल का पुर्नविकास

मैं आधुनिकीकरण तथा एमपीडी 2021 के प्रावधनों के अनुसार शिवाजी टर्मिनल का विकास न.दि.न.परिषद् के एसपीवी के द्वारा विश्वस्तरीय संरचनात्मकता बनाने हेतु प्रस्तावित करता हूँ। एसपीवी डिजाइन, भवन तथा वित्त आधर (डीबीएपफ) पर सुविधओं का विकास करेगा।

4.7.2 अन्य व्यवसायिक विकास परियोजना

4.7.2.1 न.दि.न.परिषद् फायर ब्रिगेड लेन पर सेवा केन्द्र भवन का निर्माण पूर्ण किया गया, उसी का एक हिस्सा केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रम को लाइसेंस आधर पर दिया जाएगा। न.दि.न.परिष्झद् ने खान मार्किट पर भूमि का एक प्लाट लिया हैं, जो डीबीएपफ आधर पर न.दि.न. परिषद् के एसपीवी बहुस्तरीय पार्किंग के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं। यशवंत–प्लेस पर व्यवसायिक काम्पलैक्स के विकास हेतु, सैद्धान्तिक रूप से परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिस हेतु बजट–अनुमान वर्ष 2017–18 ₹ 20 करोड़ का प्रावधन रखा गया हैं।

4.7.2.2 गोल मार्किट के पुर्नरूद्धार का कार्य लम्बी अवधि से लंबित है। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में सलाहकार वास्तुविद् की रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना हैं। वर्ष 2017–18 में कैफेटेरिया के साथ इसका एक शहरी आर्ट गैलरी (सिटी आर्ट गैलरी) के रूप में पुर्नरूद्धार करने का कार्य आरंभ किया जाएगा।

4.7.3 पूर्वी किदवई नगर का विकास

पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली के पुर्नविकास के भाग के रूप में, न.दि.न.परिषद् ने भूमि एवं विकास कार्यालय से मार्किट का कब्जा ले लिया है, दुकाने जिनमें तत्कालीन दुकानों के संबंधित लाइसेंस धारकों से पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली के पुर्नविकास से पूर्व, लाटरी ड्रा द्वारा आवंटित किया गया आवंटी दुकानों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में हैं।

5 सामाजिक विकास

5.1 चिकित्सा सेवाएँ

5.1.1 वर्ष 2016–17 में संरचनात्मकता से संबंधित चिकित्सा सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु, बहुत से उपायों का प्रस्ताव किया गया। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही हैं कि विद्यमान चिकित्सा सुविधओं के क्लाउड–आधरित एकीकरण द्वारा स्वास्थ्य पद्धति की दक्षता तथा प्रभावशीलता में सुधार हेतु अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही हैं कि अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के सभी मॉड्यूल सभी न.दि.न.परिषद् अस्पतालों, पोलीक्लिनिक तथा डिस्पेसरियों में जनवरी–2017 की समाप्ति तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना हैं।

5.1.2 चरक पालिका अस्पताल (सीपीएच) में सीटी तथा एमआईआई सेवाओं उपलब्ध कराने हेतु निविदा पीपीपी मॉडल के अंतर्गत जारी की गई तथा कार्य मार्च 2017 तक सौंपे जाने की संभावना है। चरक पालिका अस्पताल में आपातकालीन आपरेशन थियेटर बनाया गया। न.दि.न.परिषद् के सफाई–सेवकों की नियमित जांच की जा रही है, तथा यह एक सतत् प्रक्रिया हैं जोकि हमारे कर्मचारी स्वास्थ्य जीवन जीने हेतु सभी आवश्यक निवारक उपाय किए जाएगें। क्लिनिक्ल प्रशिक्षण कार्यक्रम बीडीएस स्नातकों हेतु आरंभ किया गया। भारी मांग को देखते हुए, बीडीएस स्नातकों की क्लिनिक्ल प्रशिक्षुता की संख्या आठ तक बढ़ा दी गई, जिसमें से एक सीट न.दि.न.परिषद् कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। मंदिर मार्ग पर एक स्टेट ऑफ आर्ट आयुष पोलीक्लिनिक (आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी) स्थापित किया गया।

5.1.3 न.दि.न.परिषद् ने ऑनलाइन उपलब्ध चिकित्सीय स्टॉकों की विस्तृत सूची बनाई हैं, जोकि न केवल दक्ष सूची प्रबन्धन बनाने में सहायक होगा तथा पारदर्शिता भी लाएगा जिसके द्वारा सभी उपयोगकर्त्ता जान पाएगे कि दवाईयां वास्तव में उपलब्ध हैं या नहीं।

5.1.4 मॉड्यूलर इंटरियर्स के साथ दो अत्याधुनिक आपरेशन थियेटर वाले अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण हेतु कार्य तथा चरक पालिका अस्पताल में आपरेशन पश्चात् स्वास्थ्य लाभ इकाई तथा आईसीयू इकाई हेतु नवीनतम उपकरण दिए गए जिसके लिए बजट – अनुमान वर्ष 2017–18 में ₹ 7.5 करोड़ का प्रावधन किया गया है। कार्य वर्ष 2017–18 में पूर्व होने की संभावना है।

5.1.5 225 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी चरक पालिका अस्पताल चरण–II के निर्माण हेतु 3, भूमिगत तल, भूतल तथा छः ऊपरी मंजिलों सहित, ₹ 278.50 करोड़ हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति के लिए मामला परिषद् के समक्ष प्रस्तुत हैं। परियोजना हेतु निधि बजट–अनुमान वर्ष 2017–18 में किया जाएगा। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, भारत सरकार के साथ, सहयोग में विकास की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

5.1.6 आयुष पोलिक्लिनिक की भारी मांग को देखते हुए, मन्दिर मार्ग नई दिल्ली पर एक और आयुष पोलिक्लिनिक खोलने का प्रस्ताव है। खैराती क्लिनिक नई दिल्ली में नए कल्याण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2017–18 में पालिका प्रसूति अस्पताल में होम्योपैथिक ओपीडी की स्थापना करना प्रस्तावित किया जाता है।

5.1.7 नेताजी नगर, सरोजिनी नगर तथा नौरोजी नगर कालोनियों का शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनर्विकास किया जा रहा है। मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ कि इन

कालोनियों का पुनर्विकास करते समय, न.दि.न.परिषद् ने शहरी विकास मंत्रालय को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयुष अस्पताल एवं अन्वेषण केन्द्र की स्थापना हेतु क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव करेगा।

5.1.8 चरक पालिका अस्पताल में एक मेन्टेनेन्स हेमोडायलिसिस यूनिट (एमएचडी) की स्थापना करना प्रस्तावित किया जाता है जोकि आपतकालीन सेवा यूनिट के साथ संबंद्ध किया जाएगा तथा उनके साथ हेमोडायलिसिस रोगियों की अद्यतन स्थिति हेतु चौबीस घंटों के लिए एक प्रयोगशाला बैकअप होगा।

5.1.9 आगे वर्ष 2017–18 में एक मैडिकल गैस पाईपलाइन के साथ मैडिकल गेमों जैसे अक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, संकुचित मैडिकल तथा सर्जिकल एयर तथा वेक्यूम की आपूर्ति के साथ निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

5.1.10 आगे वर्ष 2017–18 में इनबिल्ट ऑपरेशन थिएटर सुविध सहित अत्याधुनिक एम्बूलेंस की खरीद का प्रस्ताव किया जाता है।

5.1.11 न.दि.न.परिषद् देश में पहली नगरपालिका निकाय है जिसके सभी क्लिनिकों को एनएबीएच मान्यता प्राप्त है।

5.1.12 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 137.77 करोड़ का बजट प्रावधन रखा गया है जिसमें से ₹ 11.41 करोड़ पूँजीगत व्यय के लिए है।

5.2 शिक्षा

5.2.1 शिक्षा में सुधार करने के लिए डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट कक्षाओं को परम्परागत कक्षाओं को भविष्य की तकनीक में सक्षम स्मार्ट लर्न कक्षाओं में सम्मिलित कर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, संरचना तथा पेशेवर शिक्षा सामग्री विकसित की है जो कक्षा VI से XI तक सभी न.दि.न.परिषद् स्कूलों में ई–लर्निंग समाधनों को प्रदान करने के लिए वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित किया गया था। मुझे यह कहते हर्ष हो रहा है कि छठी से बारहवीं तक की सभी 444 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसी कक्षाओं में उच्च स्तरीय कम्प्यूटर्स, इन्टरएक्टिव वाइट बोर्ड, शार्ट थ्रो प्रोजेक्टर तथा अन्य हार्डवेयर भी लगाए जाते हैं। हर्ष हो रहा है कि सभी 444 कक्षाएँ छठी से बारहवीं तक कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसी कक्षाओं में उच्च स्तरीय कम्प्यूटर्स, इन्टरएक्टिव वाइट बोर्ड, शार्ट थ्रो प्रोजेक्टर तथा अन्य हार्डवेयर भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक स्कूल में एक कम्प्यूटर लैब विकसित की गई है। डिजिटल पुस्तकालयों में 10 स्कूलों के स्कूल पुस्तकालयों के उन्नयन का कार्य चालू वित्त वर्ष 2016–17 में किया जाएगा जिससे कोई भी ऑनलाइन पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है।

5.2.2 मैं इस विषय के शिक्षकों में सुधार और उनके शिक्षा कौशल का उन्नयन करने के लिए नियमित रूप में सेवाकालीन प्रशिक्षण को आरम्भ करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। इस संबंध में, वर्ष 2016–17 में प्रख्यात शिक्षाविद्, नेतृत्व कौशल में प्रशिक्षण, नियमित रूप से सलाह तथा निगरानी के साथ बातचीत के अवसर देते हुए स्कूलों के प्रधनाचार्यों तथा मुख्याध्यापिका को स्कूल नेताओं के रूप में प्रशिक्षित करने के विशेष प्रयास किए गए। इच्छुक सेवानिवृत व्यवसायिक, सुप्रसिद्ध हस्तियाँ और शिक्षाविद् (सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र से) समग्र गुणवत्ता में सुधार तथा युवा मन को विकसित करने के लिए न.दि.न.परिषद् स्कूलों में संरक्षक के लिए

आवेदन आमंत्रित किए गए। मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधनमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव श्री भूरे लाल ने पहले से ही न.दि.न.परिषद् के नवयुग स्कूल लोधी एस्टेट में संरक्षक के रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

5.2.3 वर्ष 2016–17 में किए गए कार्यकलापों का केन्द्रीय बिन्दु तक के प्रत्येक विद्यार्थी का उपलब्धि के स्तर पर मैप किया गया था। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आधर स्तर अनुकूलित सुधार योजना तैयार की गई थी और समस्त शिक्षा प्रणाली आर्थात् अध्यापकों, स्कूल प्रधनाचार्यों, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा परामर्शदाता तथा माता–पिता ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम किया। यह कार्यक्रम 60 दिनों के लिए समर्पित ध्यान के साथ चलाया गया तथा बाहरी मूल्यांकन कर्ताओं की एक टीम ने अनुपालन के निर्धरण की अगुआई की। विद्यार्थियों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार पाया गया तथा 40 प्रतिशत विद्यार्थी आधार स्तर पर थे, 62.5 प्रतिशत ऐसे विद्यार्थियों काफी हद तक उनके आधार स्तर में सुधर हुआ है।

5.2.4 निरंतर प्रयासों के साथ, नवुयग सकूलों में कक्षा XII का परिणाम 2014–15 में 79.4 प्रतिशत से वर्ष 2015–16 में 89.30 प्रतिशत हुआ तथा न.दि.न.परिषद् विद्यालयों को वर्ष 2014–15 में 78.74 प्रतिशत से वर्ष 2015–16 में 84.71 प्रतिशत का सुधर हुआ। मुझ आशा है कि यह प्रवृत्ति वर्ष 2017–18 में भी सतत् रहेगी।

5.2.5. शिक्षा की मजबूत नींव रखना व पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा का सशक्तिकरण आवश्यक है जिसके लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि कक्षा I से V की शेष 333 कक्षाओं को वर्ष 2017–18 में स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया जाए।

5.2.6 स्कूल बैग का वजन कम करने के साथ–साथ नवीनतम उपलब्ध शिक्षा अद्यतन प्रदान करने के लिए, यह परिकल्पित किया जाता है कि न.दि.न.परिषद् प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक टेबलेट होगा जिसका नियंत्रण कक्षा में ब्ल्यूटूथ जैसे टैक्नोलाजी के माध्यम से अध्यापकों के पास रहेगा जिसमें घर में भी आनलाइन शिक्षा लेने के लिए वाई–फाई की सुविधा होगी। यह प्रस्तावित किया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में नवीं कक्षा हेतु पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को एक टेबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।

5.2.7 यह प्रस्तावित किया गया कि मॉडयूल जैसे स्कूल प्रोफाइल मैनेजमेंट, स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, कर्मचारी की जानकारी, छात्रा/शिक्षक उपस्थिति, अवकाश प्रबन्धन, रिपोर्ट कार्ड, पाठ्यक्रम ट्रैकिंग छात्रा/शिक्षक उपस्थिति पर अभिभावकों/प्रशासकों को एसएमएस अलर्ट इत्यादि के साथ विद्यालय प्रबन्धन सूचना प्रणाली सहित एक स्मार्ट ई–पोर्टल, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा प्रशासकों को वास्तविक–समय अद्यतन के साथ उसी प्लेटफार्म पर लाकर एकीकृत करने के लिए आरम्भ किया जाएगा। प्रमुख आधार पर स्मार्ट क्लासरूमों की वेवकास्टिंग प्रारंभ करना प्रस्तावित किया गया। इस कार्य के लिए बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 10.00 करोड़ का प्रावधन रखा गया है।

5.2.8 औपचारिक कक्षा घंटों के उपरांत सड़क सुरक्षा, साफ–सफाई के रखरखाव, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा सहित विद्यालय में राष्ट्र निर्माण गतिविधियों को आत्मसात् करने का प्रस्ताव किया गया। गर्मी की छुट्टियों का बेहतर उपयोग के लिए तथा हॉबी क्लासिज़, गर्मी की छुट्टियों के दौरान वाइब्रैंट रूचि कक्षाओं के माध्यम से आर्ट/तकनीक आत्मसात् करने हेतु 13 विद्यालयों में वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ करना प्रस्तावित किया।

5.2.9 वर्तमान 18 बालवाड़ियों तथा क्रेशों को सशक्त किया जाएगा तथा उनकी पूरी तरह से

मरम्मत करने के उपरांत पालिका प्ले स्कूलों के रूप में, विकसित किया जाएगा। न.दि.न. परिषद् अपने निवासियों को आधुनिक प्ले स्कूलों की सुविधाएँ प्रदत्त करेगी।

5.2.10 यह प्रस्तावित किया गया कि नवीं तथा बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु निजी क्षेत्र के साथ सहयोग से एकेडमिक सहित कौशल विकास पाठ्यक्रम, जैसे–3डी प्रिटिंग तथा रोबोटिक आरंभ किए जाए।

5.2.11 न.दि.न.परिषद्/नवयुग विद्यालयों में शैक्षणिक, पाठ्येत्तर गतिविधियों, भवन रखरखाव तथा हरित सहित सभी पक्षों में जो बेहतर करेगा, उसे क्रमशः ₹ 5 लाख, ₹ 3 लाख तथा ₹ 1 लाख के नकद ईनाम के साथ न.दि.न.परिषद् की बेस्ट स्कूल रनिंग ट्राफी (स्वर्ण, रजत तथा कांस्य) प्रारंभ करना प्रस्तावित किया गया। तृतीय पार्टी जैसाकि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इण्डिया के द्वारा मानक साँचा (स्टेण्डर्ड टैम्पलेट्स) के आधर पर ट्राफी दी जाएगी।

5.2.12 खेलों की संरचना

5.2.12.1 जैसाकि खेल शरीर को दुरूस्त रखता है तथा विद्यार्थी के सम्पूर्ण विकास के लिए खेल आवश्यक है, इसलिए वर्ष 2017–18 में न.दि.न.परिषद् विद्यालयों में खेल सुविधाओं के उन्नयन को लिया जाएगा। मैं यह बताना चाहूँगा कि 12 विद्यालयों में 8 खेलों के लिए विद्यालय घंटों के उपरांत न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि सामुदायिक बच्चों के लिए भी "स्पोटर्स कोचिंग एकेडमी" खोली गई है।

5.2.12.2 10 बहुदद्देशीय खेल के मैदानों के विकास के लिए, खराब प्रतिक्रया के कारण निविदा को पुनः आमंत्रित किया गया तथा पुनः चलायमान किया गया। कार्य वर्ष 2017–18 में पूर्ण होना प्रस्तावित है।

5.2.12.3 विकलांगों के लिए खेल गतिविधियों के आयेाजन हेतु साल में ₹ 15 लाख अध्यक्ष, न.दि.न.परिषद् खेल कोष के लिए प्रस्तावित किए गए।

5.2.13 शिक्षा क्षेत्र हेतु बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 207.30 करोड़ का प्रावधन रखा गया, जिनमें से ₹ 13.67 पूँजीगत व्यय हेतु है।

5.3 कौशल विकास

5.3.1 प्रधनमंत्री कौशल केन्द्र (पीएमकेके) के गठन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन (एनएसडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए तथा पीएमकेवीवाई एवं रीकागनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम (आरपीएल) के अन्तर्गत कोर्स शुरू किए गए। एनएसडीसी, मोती बाग, नई दिल्ली में विश्वस्तरीय कौशल विकास केन्द्र के गठन में न.दि.न. परिषद् को सहायता करेगा।

5.3.2 न.दि.न.परिषद्, प्रधनमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अन्तग्रत स्वास्थ्य क्षेत्र में आए कोर्स शुरू करेगा। दंत सहायक का कौशल विकास कोर्स, पालिका स्वास्थ्य केन्द्र, धरम मार्ग, नई दिल्ली में आरम्भ किया जाएगा। सम्मिलित ग्रोथ हेतु आईसीआईसीआई फाउडेंशन ने विक्रय कौशल/रिटेल सेल्स तथा कार्यालय प्रशासन में तकनीक एवं कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कर समावेशन हेतु प्रस्तावित किया। सूर्यामित्र कौशल विकास कार्यक्रम, भारत सरकार के सोलर उर्जा राष्ट्रीय संस्थान के साथ वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ होगी।

5.4 संस्कृति एवं मनोरंजन सहभागिता

5.4.1 वर्ष 2016–17 में, न.दि.न.परिषद् ने बीआरआईसीएस रोज गार्डन के नाम से शंतिपथ पर एक रोज़ गार्डन विकसित किया है, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री, शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन एवं सूचना एवं प्रभारण, भारत सरकार ने उद्घाटन किया था। न.दि. न.परिषद् ने जीजेटिक आकार का स्टेनलेस स्टील का चरखा म्यूजियम विकसित किया है, जो कनाट प्लेस स्थित पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। न.दि.नपरिषद् पालिका बाजार के ऊपर एक पब्लिक प्लाजा का विकास कर रहा है जिसमें वाई–फाई, ओपन एयर कैपफेटेरियो, इन्ट्रोक्टिव पैनल, मोबाइल/लैपटाप चार्जिंग सुविधाओं जैसी सुविधाएँ जैसी सुविधाएँ है, जिसके चालू वित्तवर्ष 2016–17 में पूर्ण हो की संभावना है।

5.4.2 आगे नवीन, परस्पर संवाद तथा सृजनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए मार्किट क्षेत्रों में सांस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्याकलापों का विकास करना प्रस्तावित है, जहां सीखना एवं सृजन शीलता अपना स्थान रखती है। न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में विरासती सैर पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत आरंभ की जायेगी।

5.4.3 वर्ष 2016–17 में न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में 17 विभिन्न स्थानों पर आउटडोर जिमों के प्रस्तावित संस्थापन के लिए 58 आउटडोर जिम संस्थापित किए जा रहे हैं तथा कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेगा आगे 12 स्थानों में अतिरिक्त आउटडोर जिम बनाने प्रस्तावित है जिसके लिए बजट अनुमान वर्ष 2017–18 में ₹ 1 करोड़ का प्रावधन रखा गया है।

5.4.4 कनॉट प्लेस नई दिल्ली में पणधारियों के साथ विचार–विमर्श करके पैदलीकरण को कार्यन्वित किया जाना प्रस्तावित है।

5.4.5 न.दि.न.परिषद् विद्यमान स्रोतों के बेहतर प्रयोग को करने हेतु "खुशनुमा क्षेत्र" बनाते हुए इण्डिया गेट पर स्थापित चिल्ड्रन पार्क को बदलना प्रस्तावित किया। डीयूएसी तथा सेन्ट्रल विस्टा कमेटी के साथ परामर्श से हेरीटेज रेलवे कोच के उचित स्थापन के साथ मिनी रेलवे स्टेशन कम कैपफेटेरिया को चलाने तथा डिजाईन, कार्यान्वित, स्टेट ऑफ आर्ट आभासी वास्तविक थियेटर का विकास, विद्यमान पुस्तकालय का पुर्नउद्धार तथा विद्यमान टैंक एक्वेरियम का आधुनिक टनल एक्वेरियम में उन्नयन परिकल्पित है। यह इस प्रसिद्ध पार्क के अनूठे अनुभव तथा मनोरंजन क्षमता में वृद्धि करेगा। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर कार्यान्वित होनी प्रस्तावित है।

6 पर्यावरणीय स्थिरता

6.1 हरित न.दि.न.परिषद्

6.1.1 न.दि.न.परिषद् की स्थिरता योजना – हरियाली की पहल को बढ़ाने तथा स्रोतों के संरक्षण को बढ़ाने हेतु, न.दि.न.परिषद् स्थिरता योजना आरंभ करना प्रस्तावित किया गया है जिसके लिए ₹ 7.5 करोड़ का प्रावधन बजट अनुमान 2017–18 में रखा गया है।

6.1.2 न.दि.न.परिषद् ने स्टेकहॉल्डरों के साथ लगभग 7.5 लाख पौंधे रोपित करना तथा वर्ष 2016 में गहन वृक्षारोपण अभियान आरम्भ किया है। लोदी कॉलोनी तथा नेताजी नगर में 2 हर्बल उद्यान तथा शांति पथ पर एक गुलाब का उद्यान विकसित किया गया है।

6.1.3 वर्ष 2017–18 में गहन वृक्षारोपण अभियान को जारी रखना भी प्रस्तावित किया गया है तथा न.दि.न.परिषद् में हरियाली की वर्तमान स्थिति को निर्धरित करने हेतु तीसरी पार्टी से हरित सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

6.1.4 खड़े उद्यानों के विकास के कार्य को आरंभ किया गया, वर्ष 2017–18 में इसे अन्र्तराष्ट्रीय स्तर के अनुसार बनाने हेतु आगामी स्तर को प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

6.1.5 छटाई मशीनों को 10 जल टैंकरों, स्वतः हस्त उपकरणों इत्यादि के क्रय सहित दक्षता तथा प्रभावशीलता को सुधारने हेतु उद्यान उपकरणों का यात्रिकीकरण तथा सुविधाएं वर्ष 2016–17 में आरंभ की गई। मुख्य उद्यानों तथा पार्कों में बैठने के बैंचों को बढ़ाने हेतु विक्टोरिया प्रकार के बैंच तथा एमएस कूड़ेदान स्थापित किए गयें। उद्यान उद्देश्यों हेतु ट्रीटिड जा आपूर्ति को बढ़ाने हेतु 6 ट्रेक्टर (2 बड़े 4 छोटे) तथा 4 टेंकर (2 बड़े 4 छोटे) लगाने प्रस्तावित किए हैं।

6.1.6 दो स्टेट ऑफ आर्ट आधुनिक नर्सरियों हेतु राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड के साथ परामर्श से ₹ 76 लाख की लागत पर कार्य सौंपा गया, तथा वर्ष 2017–18 के प्रथम त्रौमासिक की समाप्ति तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

6.1.7 रोज़ गार्डन में आवाजाही में अत्याधिक वृद्धि हुई है, सार्वजनिक गार्डन क्षेत्र के आस–पास जलपान की उपलब्ध्ता न होने के कारण असुविधा का सामना कर रही है। अतः वर्ष 2017–18 में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा करने हेतु शांति पथ पर रोज़ गार्डन (गार्डनों) में खुले जैव कैफिटेरिया को खोलना प्रस्तावित किया गया है।

6.1.8 वर्ष 2017–18 में तुगलक क्रिसेन्ट पर सिटी लेवल पार्क को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। मामला भूमि को न.दि.न.परिषद् को स्थानांतरित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।

6.2 जन स्वास्थ्य विभाग

6.2.1 अखिल भारतीय रूप में न.दि.न.परिषद् ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2015 में 14वें स्थान से स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में चौथे स्थान पर आकर अपनी स्थिति में सुधार किया है, आगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 चल रहा है तथा इस संबंध में न.दि.न.परिषद् ने अपने सभी अनिवार्य प्रयास किए हैं।

6.2.2 न.दि.न.परिषद् ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 नवम्बर, 2016 को "खुले में शौच मुक्त" घोषित किया है।

6.2.3 वैश्विक मानकों के साथ नई दिल्ली को स्वच्छ, हरित तथा रहने योग्य राजधनी में बदलने हेतु, रियो पैरालिम्पिक्स पदक विजेता तथा अर्जुन पुरस्कार विजेताओं सुश्री दीपा मलिक एवम् पहली दिव्यांग महिला को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई हेतु सुश्री अरूणिमा सिन्हा को स्वच्छ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे, न.दि.न.परिषद् के शुभंकर (मास्कोट) स्वच्छ न.दि.न.परिषद् अभियान को बढ़ावा देने के लिए डिजाईन तथा तैनात किए गये।

6.2.4 न.दि.न.परिषद् ने 28 उपस्थिति केन्द्र निर्मित किये जिनमें उपस्थिति की सुविधाएं पेयजल, विश्राम स्थल, पृथक महिला एवं पुरूष शौचालय दिये गये है जो देश में अपने प्रकार की प्रथम परियोजना है, आगे, 20 उपस्थिति केन्द्र निर्माण के अन्तर्गत है तथा चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जायेगें।

6.2.5 न.दि.न.परिषद् ने व्यवसायिक तथा संस्थागत् क्षेत्रों से द्वार–द्वार नगर पालिका ठोस कूड़ा संग्रहण को बढ़ावा दिया। न.दि.न.परिषद् ने जंगल तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 के आधर पर उपयोगिता प्रभारों को लगाना आरंभ किया गया। न.दि.न.परिषद् ने ऑरगैनिक कूड़े से पिंलजी गाँव में 500 किलो ग्राम/दैनिक क्षमता के बॉयो–मैथेनाईजेशन प्लांट हेतु स्थापना के लिए सुविधाभोगियों का चयन किया, कार्य शीघ्र ही सौंपे जाने की संभावना है। वर्ष 2017–18 में ओखला में औरगैनिक कूड़े को मैथेन गैस में परिवर्तित करने हेतु 10 टन प्रतिदिन क्षमता का बॉयो–मैथेनाईजेशन प्लांट बनाना प्रस्तावित किया।

6.2.6 न.दि.न.परिषद् ने वैज्ञानिक संग्रहण तथा निर्माण तथा विधवंस कूड़े के निपटान के लिए (सीएण्डडी वेस्ट) आरएपफआईडी टैंग वाले वाहनों के द्वारा सुविधाभोगियों का चयन किया हैं। कार्य ₹ 68 लाख की लागत पर 6 कूड़ेदान उठाने वाली मशीनों को उपलब्ध कराने हेतु सौंपा गया। आगे, स्वच्छता में जुड़े वाहनों हेतु जीपीएस वाहन ट्रैकिंग आरंभ की गई। दो स्थान ई–कूड़े के निपटान हेतु चिन्हित किए गए है तथा निःशुल्क ऑन कॉल सुविध गैर सरकारी संस्थान के सहयोग में न.दि.न.परिषद् द्वारा ई–कूड़े के वैज्ञानिक निपटान हेतु बढ़ाई गई है। न.दि.न.परिषद् ने सीएण्डडी कूड़ेदान तथा भुगतान के आधर पर नगरपालिका ठोस कूड़ा हेतु मांग पर सेवाएं आरंभ कर दी है।

6.2.7 यांत्रिकीकृत सफाई रात्रि में तैनात की गई है तथा वर्ष 2017–18 में ऐसे यांत्रिकीकृत सफाई को बढ़ाने हेतु उचित क्षमता के तीन और यांत्रिकीकृत सफाईकर्मी पारिश्रमिक पर लेने प्रस्तावित है।

6.2.8 यह प्रस्तावित किया गया कि पाँच निवासियों कॉलोनियों, अर्थात् जोर बाग, पंडारा पार्क, बापा नगर, काका नगर तथा गोल्फ लिंक पर संबंधित आवास कल्याण संस्थानों के सहयोग से स्रोत पर कूड़े का पृथकीकरण, औरगेनिंक कूड़े की खाद, रीसाइक्लिंग इत्यादि प्रस्तावित है, अधिकतम संभावित सीमा तक इन कॉलोनियों को शून्य कूड़ा कालोनियां में बदलने के लिए वर्ष 2017–18 में कार्य किया जायेगा।

6.2.9 लोदी गार्डन तथा नेहरू पार्क को गीले सफाई उपकरण, फूल बेड में पलवार, रात्रि सफाई इत्यादि का प्रावधन करते हुए धूल मुक्त बनाना प्रस्तावित है।

6.2.10 वर्ष 2016–17 में 392 स्टेनलैंस स्टील तथा 730 मिल्ड स्टील कूड़ेदान स्थापित किए गये, 800 स्टेनलैंस स्टील कूड़ेदान तथा सभी मुख्य सड़कों मार्किट तथा पार्कों/उद्यानों में 1000 मिल्ड स्टील पॉउडर कोटिड कूड़ेदानों का कार्य सौंपा गया जिसके चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण होने की संभावना है।

6.2.11 न.दि.न.परिषद् ने प्लास्टिक की बोतलों के वैज्ञानिक निपटान के लिए कनॉट प्लेस में एक रिवर्स वेंडिग मशीन शुरू की है। वर्ष 2017–18 में परिषद् क्षेत्र में ऐसी मशीनों को लगाने का प्रस्ताव है।

7 टीम एनडीएमसी

7.1 न.दि.न.परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में जमीनी स्तर के कर्मचारियों को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति देने के लिए टोकियो, सिओल तथा सिंगापुर में तैनात किया वर्तमान वित्तीय वर्ष में जमीनी स्तर के कर्मचारियों को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति हेतु मार्च 2017 में चीन भेजा जाएगा, वर्ष 2017–18 में अन्य जमीनी स्तर के कर्मचारियों को कार्य संस्कृति में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए बेहतर अभ्यास पहुंचाने हेतु अन्य अन्तर्राष्ट्रीय शहरों में भेजा जाएगा। इसके लिए बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 1 करोड़ का प्रावधन है।

7.2 कौशल/ज्ञान तथा जॉब आवश्यकताओं के मध्य अन्तर को भरने के लिए, तथा कर्मचारियों के कौशल/ज्ञान के मानकों में सुधर हेतु, राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन के सहयोग से न.दि.न.परिषद् के सभी विभागों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव किया गया। ऐसा ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन के साथ मालियों के लिए वर्ष 2016–17 में आयोजित किया गया था। आगे कर्मचारी को स्वंम में सुधर के लिए ऑनलाईन शैक्षणिक/कौशल विकास कोर्स हेतु पंजीकृत करने का भी प्रस्ताव रखा गया।

7.3 वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कौशल विकास के साथ सहयोग से मालियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए, तथा उनके कार्य के प्रदर्शन के दौरान अपेक्षित कौशल तथा ज्ञान के अन्तर को भरने के लिए ऐसे प्रशिक्षणों को निरंतर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया।

7.4 वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्थाई मस्टर रोल तथा अस्थाई मस्टर रोल कर्मचारियों हेतु प्रधनमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधनमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को लागू किया गया।

7.5 कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति लगाने के लिए बॉयोमेट्रिक बेस अटेंडेंस प्रणाली को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। इससे दैनिक रोस्टर आधर पर जमीनी स्तर के कर्मचारी भी अपने कार्यस्थल से से अटेंडेंस लगाने में समर्थ होंगे। इससे कर्मचारियों द्वारा परेशानियों का सामना करने में भी कटौती आने की सम्भावना है, तथा इससे नैशनल आधार डाटा के साथ अभिसरण सुनिश्चित होगा।

7.6 आरएमआर/टीएमआर तथा अनुबंध आधार पर ईपीएपफ के अंशदान तथा मजदूरी की सूचना की आसानी से उपलब्धता के लिए ऐसी जानकारी न.दि.न.परिषद् की वेबसाइट तथा एनडीएमसी 311 ऐप पर उपलब्ध कराई गई है।

7.7 कार्यस्थल में कार्य करने के दौरान कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुविधओं के वृहद आकलन का प्रस्ताव रखा गया। यह कर्मचारियों से कार्यस्थल में सुरक्षा के मामलों में इनपुट प्राप्त कर एक कर्मचारी के निरीक्षण के द्वारा किया जाएगा। इसलिए इस प्रकार के सभी सुरक्षा संबंधे मामलों के समाधन के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं।

7.8 हितकारी निधि योजना का नियमित मस्टर रोल कर्मचरियों के लिए विस्तार किया गया है। मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी को ₹ 50,000 वित्तीय सहायता, कर्मचारी/नियमित मस्टर रोल स्टाफ की पुत्री के विवाह हेतु ₹ 50,000 की तथा शिक्षा में दी गई फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 3500 का भुगतान का विस्तार किया गया।

7.9 पालिका आवास की उपलब्ध्ता में पारदर्शिता लाने के लिए इसे न.दि.न.परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, जहाँ पर सभी योग्य कर्मचारी अपनी पसंद के तीन विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। उस कर्मचारी को मकान का आवंटन किया जाएगा जिसने क्वार्टर के लिए आवेदन किया है तथा वह क्वार्टर के प्रकार हेतु योग्यता में वरिष्ठतम है।

7.10 पालिका कर्मचारियों हेतु आवास

7.10.1 पालिका कर्मचारियों को आवास स्तर पर संतुष्टि में सुधर के लिए अलीगंज में टाइप–।। के 188 फ्रलेटों के निर्माण करने की योजना बनाई गई। परिषद् के अनुमोदन के उपरांत ₹ 40.33 करोड़ की लागत पर कार्य सौंपा जाएगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कार्य प्रारंभ होने की सम्भावना है। इस संबंध में बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 5 करोड़ का प्रावधन रखा गया है।

7.10.2 वर्ष 2017–18 में जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 240 क्वार्टरों का निर्माण।

7.10.3 अस्पताल में डाक्टरों को आवास उपलब्ध कराने के अनुक्रम में न.दि.न.परिषद् के डाक्टरों को अच्छी गुणवत्ता के घरों हेतु चरक पालिका अस्पताल मोती बाग में ₹ 2.93 करोड़ की लागत पर 16 फ्लेटों का निर्माण किया गया। कार्य प्रारंभ हो गया तथा दिसम्बर, 2017 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

7.10.4 अर्जुन दास कैम्प में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में अग्निशमन बेबाकी हेतु कानून में परिवर्तन के कारण विलम्ब हुआ जिसके कारण लेआउट्स तथा डिजाइन को संशोधित किया गया। अब अर्जुन दास कैम्प में टाइप–IV तथा टाइप–V के विशेष 292 फ्लेटों के निर्माण हेतु संशोधित आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ली है। परियोजना लागत ₹ 211.00 करोड़ है। परियोजना पर कार्य वर्ष 2017–18 में प्रारंभ होगा। इस संबंध में बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 15 करोड़ का प्रावधन रखा गया है।

7.10.5 सैक्टर–7 साकेत में टाइप–II के 120 फ्लैट तथा सैक्टर–6 साकेत में टाइप–III के 160 फ्लैटों के निर्माण में अग्निशमन अनापत्ति हेतु विनियमों में परिवर्तन के कारण विलम्ब हो गया, जिसके कारण लेआउट्स तथा डिजाइन संशोध्ति किए गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त की गई तथा दक्षिण नगर निगम दिल्ली से प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रतिक्षा है। इन परियोजनाओं पर कार्य वर्ष 2017–18 में प्रारंभ हो जाएगा।

7.11 भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा एकता को बढ़ावा देने में जन साधरण सहभगिता में वृद्धि पर वर्कशॉप

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा एकता को बढ़ावा देने के लिए जन साधरण सहभागिता में वृद्धि हेतु सीवीसी श्री वी.के. चौधरी की अध्यक्षता में दिल्ली विकास प्राधिकारण तथा सभी 5 शहरी स्थानिय निकायों (यथा न.दि.न.परिषद्, पूर्वी उत्तरी तथा दक्षिणी नगर निगम तथा दिल्ली कैंट बोर्ड) के साथ एक वर्कशाप आयोजित की।

8 वित्तीय स्थिरता

8.1 एनडीएमसी क्रेडिट रेटिंग

न.दि.न.परिषद् ने वर्ष 2016–17 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मैसर्स केयर लिमिटेड से एए+ क्रेडिट रेटिंग प्राप्ति की।

8.2 पेंशन निधि

8.2.1 पेंशन के भुगतान के लिए संशोधित अनुमान 2016–17 में ₹ 320 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2017–18 में ₹ 330 करोड़ का प्रावधन रखा गया।

8.2.2 जैसा कि न.दि.न.परिषद् की पेंशन भुगतान देयता में प्रति वर्ष वृद्धि होती है, न.दि.न. परिषद् की अनुकूलित लागत पर नियमित आधर पर पैंशन देयता मिलने के अनुक्रम में पेंशन निधि के सृजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में एक बीमांकिक अध्ययन आयोजित किया गया।

8.2.3 बीमांकिक अध्ययन के आधर पर स्थिरता रूप में न.दि.न.परिषद् को पेंशन देयता के लिए वर्ष 2017–18 में पेंशन निधि का सृजन किया जाएगा।

8.3 लेस कैश टू कैश लेस

8.3.1 न.दि.न.परिषद् अपनी वेबसाइट के माध्यम से करों तथा प्रभारों को ऑनलाइन स्वीकृत करती है। डिजिटल पद्धति द्वारा लेन देन करने के भारत सरकार के मिशन के साथ संरेखित, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, चैक, डिमाड ड्राफ्ट, नेटबेंकिग, एनईएपफटी, आरटीजीएस इत्यादि, लेन देनों, भुगतान की प्राप्ति जैसे पीओएस, क्यूआर कोड, वॉलेट, यूपीआई, यूएसएसडी, इत्यादि हेतु भारत सरकार द्वारा आरंभ अन्य कैशलेस पद्धतियाँ सभी काउंटर्स पर शुरू की गई हैं जहाँ पर न.दि.न.परिषद् शतप्रतिशत कैशलेस लेन देन करती है।

8.3.2 मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि न.दि.न.परिषद् को ऑनलाइन भुगतान करते समय नागरिकों पर कोई लेन–देन प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

8.4 नगरपालिका बाण्ड की स्थापनाः– वर्ष 2017–18 के न.दि.न.परिषद् स्मार्ट सिटी एसपीवी ने वित्त स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को ₹ 500 करोड़ नगरपालिका बाण्ड जारी करके निधि की स्थापना करेगी।

8.5 ई–पफाइनेनशियल प्रणाली

न.दि.न.परिषद् ने ई–फाइनेनशियल प्रणाली में बजट माड्यूल के माध्यम से बजट के आनलाइन प्रस्तुतीकरण आरम्भ किया। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह बजट बजट माड्यूल का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है।

9. अन्य पहल

9.1 सम्पदा मामलों की नीति की वृहद् समीक्षा

9.1.1 एक पारदर्शी नीति तैयार की गई थी तथा इस संबंध में नीति परिपत्रा दिनांक 16.8.2016 को जारी किया गया था। निर्धरित नीति का उद्देश्य पारदर्शिता और सरलीकरण लाना है। नीति निर्विघ्न तथा पारदर्शी नवीकरण को सक्षम बनाती है।

9.1.2 दिनांक 16.8.2016 की नीति के अनुसरण में, 200 से अधिक सम्पतियों के लाइसेंसों का नवीकरण किया गया। सभी लम्बित मामलों पर शीघ्रता से निर्णय लिया गया है। नीति लालफीताशाही तथा पक्षपात को समाप्त करेगी।

9.1.3 न.दि.न.परिषद् सक्रिय रूप से होटलों जैसे एशियन होटल, प्रोमिनेन्ट (कनाट) होटल, आईएचसीएल (होटल ताज मानसिंह), सी.जे. इन्टरनेशनल (होटल ली मेरीडियन) से संबंधित न्यायालय मामलों के पीछे लगे रहे तथा परिणामस्वरूप न.दि.न.परिषद् के पक्ष में निर्णय मिला। न.दि.न.परिषद् ने ई–ऑक्शन बोली में एशियन होटल के लिए लगभग से संबंधित न्यायालय मामलों 45.8 लाख प्राप्त हुए जोकि पूर्व लाइसेंसी द्वारा भुगतान किए गए औसत मासिक लाइसेंस शुल्क से बहुत अधिक है।

9.2 योगा इन्टरनेशनल डे तथा रन फॉर यूनिटी

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि न.दि.न.परिषद् ने 25 जून 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए तथा 31 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में एकता के लिए दौड़ आयोजित कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक नेतृत्व संगठन के रूप में कार्य किया। जिसकी सभी ने सराहना की है।

9.3 ट्विन सिटी समझौता

9.3.1 सिटी ऑफ एडीलेड, साउथ आस्ट्रेलिया ने दोनों शहरों के परस्पर लाभ का ज्ञान तथा विशेषज्ञता, शेयर लर्निंग्स तथा ट्विन सिटी समझौते में मिलकर काम करने की सहमति दी हैं इस संबंध में आगामी कार्रवाई भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदन के लिए की जा रही है।

9.3.2 न.दि.न.परिषद् वैश्विक शहरों के साथ इस तरह के समझौते करने के बारे में जानकारी, विचारों, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण तथा अन्य प्रासांगिक कार्यकलापों जो न.दि.न.परिषद् तथा अन्य वैश्विक शहरों के बीच शहरी समझौते करने की सुविध की संभावना तलाश रही है।

10. प्राप्तियाँ

10.1 विद्युत वितरण से प्राप्तियाँ

10.1.1 पावर सेक्टर की समग्र वित्तीय स्थिति के सशक्तिकरण के क्रम में न.दि.न.परिषद् ने महंगे पावर वितरण स्टेशनों से महंगी पावर क्रय के स्थान पर पावर एक्सचेंजों से सस्ती पावर क्रय करना आरम्भ किया है।

10.1.2 न.दि.न.परिषद् ने 20 से अधिक मिलियन यूनिट के बावजूद वर्ष 2014–15 की अनुवर्ती अवधि की तुलना में इस कार्य नीति के कारण ₹ 150 करोड़ से अधिक की बचत की है।

10.1.3 विद्युत वितरण से कुल राजस्व प्रप्तियाँ वर्ष 2015–16 में ₹ 1174.97 करोड़ वास्तविक आंकड़ों के बदले संशोधित अनुमान वर्ष 2016–17 में ₹ 1110.72 करोड़ अनुमानित किया गया है। बजट अनुमान 2017–18 में अनुमान ₹ 1124.42 करोड़ है, डीईआरसी द्वारा पिछले संचित घाटे की वसूली के लिए अतिरिक्त सरचार्ज फ्यूल एडजस्टमेन्ट कॉस्ट की छोटी सी कटौती के कारण है।

10.2 सम्पति कर से प्राप्तियाँ

10.2.1 न.दि.न.परिषद् ने दिसम्बर 2016 में ऑनलाइन सम्पत्ति कर रिटर्न फाइलिंग प्रणाली शुरू की है जिससे करदाताओं को सम्पत्ति कर रिटर्न पारदर्शिता और सुविधाजनक तरीके से भरने की सुविधा होगी तथा यह आश्वासन के साथ कि गणना का आंकलन कर निर्धारण आदेशों के अन्तिम रूप देने के अलावा सटीक है।

10.2.2 न.दि.न.परिषद् ने सम्पति कर दरों में कोई वृद्धि किए बिना सम्पति कर संग्रहण में वृद्धि हो रही है। मुझे यह रिपोर्ट देते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2015–16 में हमने ₹ 449.04 करोड एकत्र किए हैं हमने वर्ष 2016–17 में ₹ 475.00 करोड़ के सम्पति कर संग्रहण की आशा की है जिससे लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि है। बजट अनुमान 2017–18 हेतु, हमने ₹ 490.00 करोड़ का लक्ष्य रखा है। मैं वर्ष 2017–18 हेतु सम्पति कर की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि कर का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ।

10.3 नगरपालिका सम्पतियों से लाईसेंस शुल्क से प्राप्तियाँ

10.3.1 न.दि.न.परिषद् सम्पतियाँ जिसका लाइसेंस नवीकरण/हस्तांतरण के लिए लम्बित है, पर जुलाई 2016 में परिषद् द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। परिणामस्वरूप, यह आशा की जाती है कि लाइसेंस प्राप्त नगरपालिका सम्पतियों से प्राप्तियों में वृद्धि होगी।

10.3.2 नगरपालिका सम्पतियों से लाइसेंस शुल्क हेतु संशोधित अनुमान 2015–16 में ₹ 457.45 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2015–16 में वास्तविक प्राप्तियाँ ₹ 414.24 करोड़ है। वर्ष 2016–17 हेतु संशोधित अनुमान ₹ 453.21 करोड़ है तथा बजट अनुमान 2017–18 का ₹ 518.53 करोड़ है।

निकट भविष्य में हमारे राजस्व में वृद्धि के सीमित क्षेत्र के विरूद्ध, मैं प्रस्तावित करता हूँ कि न.दि.न. परिषद् वित्तीय संसाधनों के उपयोग के लिए फालतू खर्च से बचने और अक्षमता से परहेज करने के हर संभव प्रयास करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं की नियमित आधार पर समीक्षा की जाएगी।

माननीय सदस्यगण, वर्ष 2017–18 के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों की माँग रही है, किन्तु हम प्रत्येक क्षेत्र में

सुशासन को बनाए रखने में दृढ़ संकल्प है जो हमने किया है, जिससे आप सभी तथा नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, नागरिक सहभागिता तथा स्मार्ट टैक्नोलजी के हस्तक्षेप से दुर्लभ संसाधनों की उपयोगिता संभव हो पाएगी जिसके द्वारा हम एक मजबूत और आर्थिक रूप से स्थायी नागरिक केन्द्रित संगठन के रूप में बने रहेंगे।

मैं माननीय गृहमंत्रालय, मंत्री, माननीय शहरी विकास मंत्रालय मंत्री, भारत सरकार तथा माननीय उपराज्यपाल दिल्ली से प्राप्त मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए आभार प्रस्तुत करना चाहूँगा।

मैं माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय संसद सदस्य, परिषद् के उपाध्यक्ष, माननीय विधयक तथा परिषद् के गणमान्य सदस्यों को उनके निरन्तर सकारात्मक सहयोग तथा समय–समय पर मुझे दिए गए उनके अमूल्य सुझावों हेतु ध्न्यवाद करना चाहूँगा।

मैं न.दि.न.परिषद् के सभी कार्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रदर्शन के लिए अपने साथी सहयोगियों विशेषकर सफाई सेवकों, मालियों, बेलदारों तथा लाइनमैन को उनके निरंतर समर्थन के लिए निष्ठावान ध्न्यवाद कहना चाहता हूँ।

आपका बहुत बहुत ध्न्यवाद।

जय हिन्द

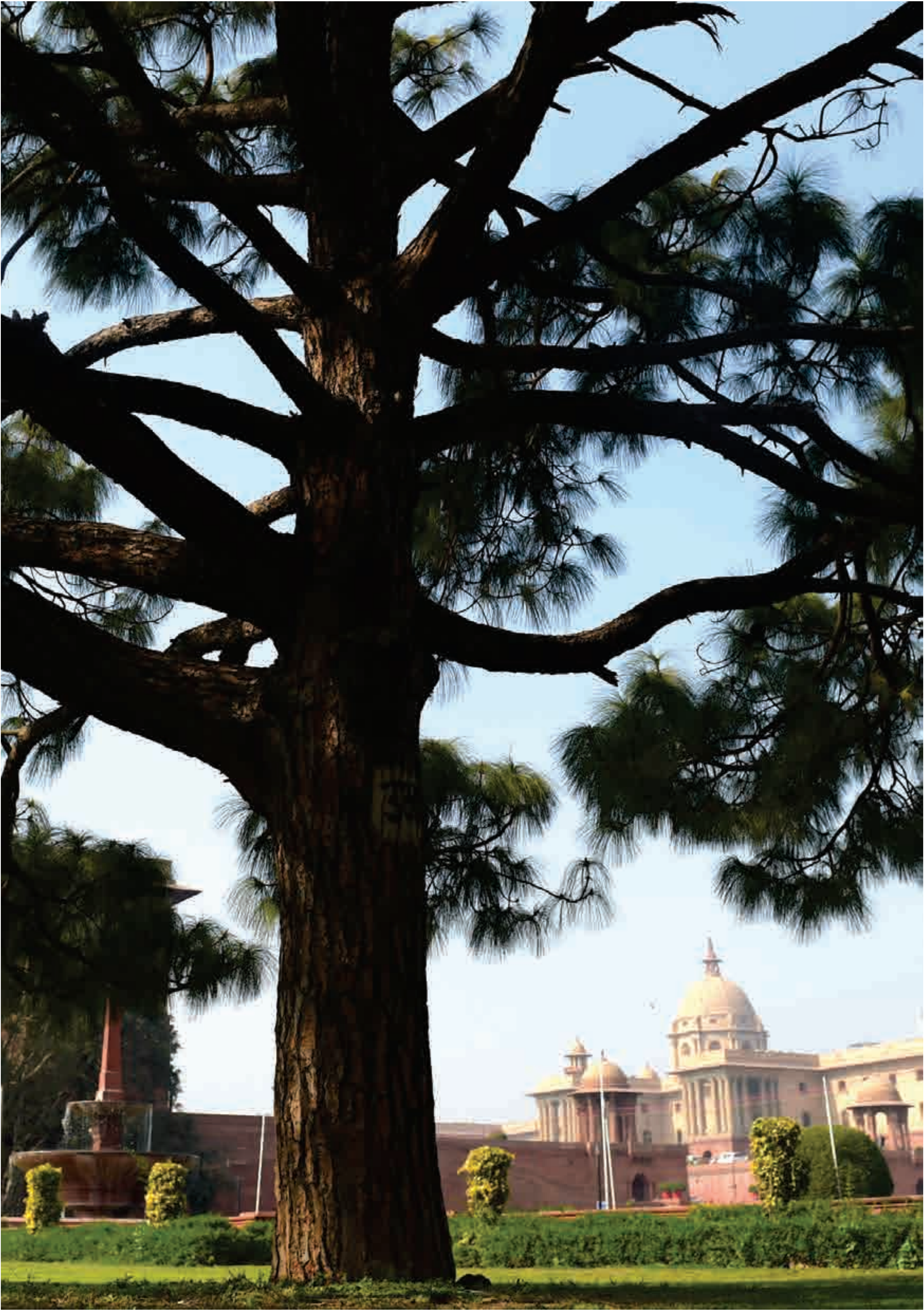

www.degree360solutions.com

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली **110001**

New Delhi Municipal Council
Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi 110001
www.ndmc.gov.in